(ख) और (ग) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा इराक के खिलाफ लगाए आर्थिक प्रतिबंधों के कारण अगस्त, 1990 से उस देश के साथ कोई भी व्यापार नहीं किया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप भारतीय निर्माण परियोजना निर्यातकों की 63 मीलियन अमरीकी डालर की देयता जिसको मार्च 1990 में हस्तांतरित आस्थगित भुगतान करार की शर्तों के अनुसार इराक से अपरिष्कृत तेल की सप्लाई के जरिए वसूल किया जाना था, इराक द्वारा नहीं चुकाया गया है। इराक के साथ वर्ष 1991 के लिए आस्थगित भुगतान करार को भी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(घ) चालू वर्ष के दौरान, अगस्त 1991 तक कुवैत को 11.81 करोड़ रु० के निर्यात किए गए हैं। निर्यात की गई मदों में इंजीनियरी वस्तुएं, चावल, वस्त्र, फल और सब्जियां, समुद्री उत्पाद, मांस आदि शामिल हैं।

विवरण

खाड़ी देशों के साथ भारत का व्यापार

वर्ष	निर्यात	आयात
1989-90	1717.17	4835.17
1990-91	1567.42	6317.83

भारतीय राज्य व्यापार निगम का कार्य-निष्पादन

377. **श्री राम जेठ मलानी :**
श्री रणजीत सिंह :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1990-91 के दौरान भारतीय राज्य व्यापार निगम का कार्य-निष्पादन संतोषजनक नहीं रहा है ;

(ख) क्या सरकार ने निगम के कामकाज में सुधार लाने की दृष्टि से कुछ कदम उठाये हैं ;

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि इस निगम में काफी संख्या में कर्मचारी और अधिकारीगण कार्यरत है ;

(ङ) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष के शुरू में इस निगम में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी थी ; और

(च) वर्ष 1990-91 के दौरान इस निगम द्वारा कितना निबल लाभ अर्जित किया गया था तथा इस वित्तीय वर्ष में इसका कुल कितना प्रशासनिक खर्च हुआ ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (ग) यद्यपि एस०टी०सी० के वर्ष 1989-90 के दौरान 1855 करोड़ रुपए के कारोबार की तुलना में 1990-91 में हुए 1756 करोड़ रुपए के कुल कारोबार में नाम मात्र की कमी हुई, पी०एस०टी०सी० कारोबार करीब 2% के बराबर लाभप्रदता बनाए रख सका। वर्ष 1989-90 के दौरान 752 करोड़ रुपए की तुलना में 1990-91 में 369 करोड़ों रुपए का निर्यात हुआ। व्यापार नीति के हाल ही में किए गए परिवर्तनों के अनुसार समग्र कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के उद्देश्य से एस०टी०सी० के सम्मिलित उद्देश्यों को नियमानुसार पुनः परिभाषित किया गया है :

- प्रतिस्पर्धी व्यापार वातावरण में काम करने वाले एक प्रधान अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार घराने के रूप में उभरना।
- नियोजित पूंजी पर पर्याप्त सुनिश्चित करना :
- सार्वजनिक नीति के एक प्रभावी उपकरण के रूप में कार्य करना।

दक्ष कार्य-संस्कृति को सुनिश्चित करने हेतु करियर प्लानिंग। पर जोर देते हुए प्रबंधन की एक सहानुभूतिपूर्ण एवं सहयोग पूर्ण शैली विकसित करना

–लघु और कुटीर क्षेत्रों को कच्चा माल की आपूर्ति उनके उत्पादों का विपणन इत्यादि जैसी समर्थन सेवाएं प्रदान करना। संशोधित सम्मिलित उद्देश्यों के परिपेक्ष्य में एल०टी०सी० ने वर्ष 1991-92 के लिए अपनी क्रिया योजना की रूपरेखा तैयार की है जिसमें निम्नलिखित पर जोर डाला गया है :–

–सीधे बेचना और खरीदना

–निर्यात के नए क्षेत्रों का पता लगाना।

–निजी आपूर्ति आधार का सृजन।

–तीसरे देशों के साथ व्यापार इत्यादि।

(घ) और (ङ) चालू वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में एस०टी०सी० के कर्मचारियों की स्थिति निम्नानुसार है :–

दिनांक 1-4-91 के अनुसार

प्रबंधक	905
कर्मचारी	1627
कुल	2532

(च) स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन द्वारा 1990-91 के दौरान कमाया गया कर पूर्व निवल लाभ 34.6 करोड़ रुपए हुआ। स्थापना प्रशासन और वर्ष 1990-91 के लिए अन्य लागत सहित 38.2 करोड़ रुपए हुआ।

Trade deficit during current year

378. SHRI DIPEN GHOSH: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) what is the foreign trade deficit expected during this year;

(b) whether this includes imports for defence;

(c) what is the expected overall Balance of Payment deficit; and

(d) the manner in which this deficit is expected to be covered?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) According to the provisional figures, India's trade deficit has come down from Rs. 4234 crores during April–September, 1990 to Rs. 2356 crores during April–September 1991. It is difficult to precisely estimate the trade deficit for the financial year 1991-92 at this stage.

(b) The trade figures include only the merchandise trade that pass through the customs, without any distinction being made whether they are for defence purposes or otherwise.

(c) and (d) The deficit in trade account is to be financed by net invisibles and flows in the Capital Account in order to maintain the level of foreign currency reserves. Hence the question of a deficit in overall balance of payment as such does not arise.

Government's stand on drafts agreement on special 301

379. SHRI M. A. BABY: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether a draft agreement on Special 301 was handed over by the U.S. Trade representative during his visit to Washington;

(b) if so, what are the details of this draft agreement; and

(c) what is Government's decision/stand on the various clauses of the draft agreement?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) to (c) In the normal course of bilateral consultations the U.S. authorities handed over to the Indian